मेसर्स केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी

बनाम

हिंडन कॉपर लिमिटेड

(2006 की सिविल अपील संख्या 2562)

15 दिसंबर, 2016

[मदन बी. लोकुर, आर. के. अग्रवाल और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-धारा 48-दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली द्वारा विवाद समाधान-पार्टियों की वैधता-मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध में प्रवेश किए गए पक्षकारों के बीच बाद में विवाद-अपीलकर्ता कंपनी ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया-भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति, जिसने एन. आई. एल. अवॉर्ड दिया-इसके बाद, अपीलकर्ता कंपनी द्वारा मध्यस्थता खंड के दूसरे भाग का आह्वान-अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के सुलह और मध्यस्थता नियमों के अनुसार लंदन में मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार-धारा के तहत आवेदन। सेक्शन 48 उक्त निर्णय को लागू करने की मांग करने वाली अपीलकर्ता कंपनी द्वारा-दो स्तरीय मध्यस्थता की वैधता-आयोजितः दो स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली द्वारा विवादों का समाधान भारतीय कानून के तहत मान्य था और सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं था-पक्षों के बीच समझौते में मध्यस्थता खंड दूसरी बार मध्यस्थता के लिए सहमत पक्षों द्वारा भारत की मौलिक या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता है-मध्यस्थता समझौते के दलों को न केवल प्रक्रियात्मक कानून का पालन करने के लिए बल्कि मूल कानून पर भी निर्णय लेने की स्वायत्तता होती है।

मामलों को स्थगित करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 पक्षकारों के इरादे की सराहना करना आवश्यक है जब वे अनुबंध में मध्यस्थता खंड पर सहमत होते हैं। मध्यस्थता खंड के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि अनुबंध करने वाले पक्षों का इरादा थाः पहला, भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल के माध्यम से और भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार भारत में मध्यस्थता द्वारा अपने विवादों या मतभेदों का निपटान, और दूसरा, यदि अनुबंध करने वाले पक्षों में से कोई भी भारत में 'मध्यस्थता परिणाम' से असहमत था, तो पीड़ित पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के सुलह और मध्यस्थता नियमों के अनुसार लंदन में दूसरे मध्यस्थता के लिए अपील करने का अधिकार होगा। अपीलीय मध्यस्थता का परिणाम कानून के अनुसार कानूनी चुनौती के अधीन दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता खंड का पाठ काफी स्पष्ट और स्पष्ट है और इसकी व्याख्या पर किसी भी संदेह को स्वीकार नहीं करता है। अनुबंध करने वाले पक्षों का इरादा अनुबंध के खंड 14 में अपने विवादों या मतभेदों को हल करने के लिए दो अवसर प्रदान करना था। पहला अवसर भारत में मध्यस्थता द्वारा समझौता होगा-मध्यस्थता परिणाम और दूसरा अवसर लंदन में मध्यस्थता द्वारा होगा, जो भारत में मध्यस्थता परिणाम के खिलाफ अपील की प्रकृति में होगा। [पैरा 6] (92-डी-जी]

1.2 जबकि अनुबंध के खंड 14 ने 'मध्यस्थता परिणाम' अभिव्यक्ति का उपयोग किया होगा न कि 'मध्यस्थता पुरस्कार' अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप से पक्षों का इरादा था कि 'मध्यस्थता परिणाम' एक अवॉर्ड होगा या कम से कम भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल द्वारा दिए गए अवॉर्ड की प्रकृति में होगा। मध्यस्थता समिति के समक्ष कार्यवाही का उद्देश्य भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार संरचित और आयोजित किया जाना था। इस तरह की कार्यवाही का परिणाम अनिवार्य रूप से एक मध्यस्थता अवॉर्ड होगा, चाहे पक्षकारों द्वारा उपयोग किए गए

नामकरण की परवाह किए बिना। मध्यस्थता अवॉर्ड के अर्थ के अलावा 'मध्यस्थता परिणाम' शब्दों की व्याख्या करना मुश्किल है। [पैरा 7) (93-ए-बी]

तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, जूलियन डी. एम. ल्यू, लुकास ए. मिस्टेलिस, और अन्य, (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल 2003) पीपी। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, निगेल ब्लैकबी, कांस्टेनटाइन पार्टासाइड्स, एट अल., रेडफर्न एंड हंटर 6th एडन (® क्लूवर लॉ इंटरनेशनल; ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2015) पीपी. 501-568; अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, इमैनुएल गेलार्ड और जॉन सैवेज (संस्करण), फौचार्ड गेलार्ड गोल्डमैन (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल 1999) पृष्ठ 735-780-संदर्भित

1.3 तत्काल मामले में मध्यस्थता परिणाम में मध्यस्थता निर्णय के सभी तत्व और तत्व होते हैं। अनुबंध के खंड 14 के पहले भाग में 'मध्यस्थता परिणाम' का अर्थ भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थ पैनल द्वारा दिया गया मध्यस्थता अवॉर्ड होना चाहिए। खंड 14 की सरल भाषा विशेष रूप से भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल के निर्णय के खिलाफ 'अपील' के रूप में दूसरे मध्यस्थता का प्रावधान करती है। प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि अपील दायर करने का अधिकार केवल एक क़ानून द्वारा बनाया जा सकता है न कि पक्षों के बीच एक समझौते द्वारा। यह किसी कानून के तहत अदालतों में शुरू किए गए मुकदमे के संबंध में या सामान्य कानून अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में हो सकता है, लेकिन यह पक्षों को गैर-सांविधिक अपीलों के लिए एक समझौते में प्रवेश करने से नहीं रोकता है ताकि उनके विवादों और मतभेदों को अदालत की प्रक्रियाओं का सहारा लिए बिना अधिमानतः निपटाया जा सके। [पारस 12,14] [94-जी; 95-ए, सी-एल।

2.1 ऐतिहासिक रूप से भारत में ए एंड सी अधिनियम के अधिनियमन से पहले, दो-स्तरीय मध्यस्थता की अनुमति थी। इसका महत्व यह है कि यह माना जाना चाहिए

कि संसद को यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. कार्य समूह (जिसमें भारत एक राज्य सदस्य था) के दृष्टिकोण की जानकारी थी और यह माना जाना चाहिए कि वह विभिन्न घरेलू न्यायालयों के निर्णयों को जानती थी और फिर भी दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली को विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं करने का फैसला किया। यदि ऐसा है, तो यह न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ने का हकदार है कि ए एंड सी अधिनियम के पारित होने के बाद भी, दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली के अस्तित्व पर शायद कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यह न्यायालय इस धारणा के आधार पर निर्णय लेने का प्रस्ताव नहीं करता है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाता है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णय हैं जिन्होंने दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली को स्वीकार किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के कई निर्णयों में कहा गया है कि चूंकि ए एंड सी अधिनियम दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया को प्रतिबंधित नहीं करता है, इसलिए ऐसी प्रणाली स्वीकार्य है। [पारस 19,20] [97-बी-सी, डी-एफजे

डेढिया इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड बनाम जे. आर. डी. सिक्यूरिटीज प्रा. लिमिटेड [2002) 104 (4) बोर्न एल. आर. 932; अमीन मर्चेंट बनाम बिपिन एम. गांधी 2005 (सुपरवाइजर) अरब। एल. आर. 337; धनसुख के. सेठिया बनाम राजेंद्र कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड 2008 (1) अरब। एल ~ एल। 368 (~ ओम्बे); डोवेल लीसिनके एंड फाइनेंस लिमिटेड बनाम राधेश्याम बी. खंडेलवाल 2008 (1) बोर्न सी. आर. 768; एएनएस प्रा. लिमिटेड वी. . जयेश आर. अजमेरा 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन इलोम 1825; अंकित बिमल देवराह बनाम माइक्रोसेक कैपिटल लिमिटेड 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन बोर्न 4538; स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम इंजीनियर्स प्रोजेक्ट लिमिटेड 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2314; यू. पी. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड बनाम भारत संघ एम. ए. एन. यू./डी. ई./3452/2015; राकेश कुमार गर्ग बनाम डी. एस. ई. वित्तीय सेवा लिमिटेड. एम. ए. एन. यू./डी. ई./3339/2015;

फुएर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. 2011 (11) एस. सी. आर. 1: (2011) 8 एस. सी. सी. 333; आई. टी./लिमिटेड बनाम सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशंस नेटवर्क लिमिटेड. 2002 (3) एस. सी. आर. 1122: (2002) 5 एस. सी. सी. 510; गारिकापति वीराया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी 1957 एस. सी. आर. 488-संदर्भित।

अपने तीसरे सत्र न्यूयॉर्क के कार्य पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध प्रथाओं पर कार्य समूह की रिपोर्ट, 16-26 फरवरी, 1982, A.CN.9/216 (23 मार्च 1982); मध्यस्थता अभ्यास की पुस्तिका, स्वीट और मैक्सवेल pp.276,290-संदर्भित।

2.2 ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) और उसकी धारा 35 के संयुक्त अध्ययन पर, एक मध्यस्थता अवॉर्ड अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा जब तक कि इसे मध्यस्थता अवॉर्ड के लिए एक पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर एक सक्षम अदालत द्वारा अलग नहीं किया जाता है। यह एक प्रक्रिया के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होने के लिए एक मध्यस्थता अवॉर्ड के लिए पक्षों की स्वायत्तता को बाहर नहीं करता है जिसके द्वारा मध्यस्थता अवॉर्ड पर किसी अन्य मध्यस्थ या मध्यस्थों के पैनल द्वारा अपील के माध्यम से पुनर्विचार किया जा सकता है और उस अपील के परिणाम को पक्षकारों द्वारा अंतिम और ए एंड सी अधिनियम द्वारा प्रदान की गई चुनौती के अधीन बाध्यकारी होने के लिए स्वीकार किया जाता है। यह ठीक वही है जिस पर पक्षकार वास्तव में सहमत हुए हैं और उनके आपसी निर्णय का सम्मान करने और उनके समझौते की वैधता को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। (पैरा 27) (101-सी-डी)

2.3 यह तथ्य कि किसी निर्णय को चुनौती देने के लिए किसी पक्ष के लिए अदालत का सहारा उपलब्ध है, वास्तव में पक्षों को विवादों और मतभेदों के शीघ्र

निपटारे के इरादे से किसी निर्णय पर पारस्परिक रूप से सहमत होने से नहीं रोकता है। ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समुदाय का इरादा एक पक्ष को कई मंचों पर एक अवॉर्ड को चुनौती देने के लिए एक मध्यस्थता समझौते के अधीन करने से बचना है, जैसे कि एक दीवानी अदालत में कार्यवाही के साथ-साथ मध्यस्थता क़ानून के तहत। इसका उद्देश्य पक्षों की स्वायत्तता को कम करना या उन्हें अपीलीय मध्यस्थता जैसे निवारण के किसी अन्य स्वीकार्य तरीके को अपनाने से रोकना नहीं है। पैरा 281 [101-ई-एफजे

2.4 ए एंड सी अधिनियम की धारा 35 में "अंतिम और बाध्यकारी" खंड का मतलब सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए अंतिम नहीं है। यह अवॉर्ड एक सीमित संदर्भ में बाध्यकारी है। जब तक इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक भारत में दूसरी बार मध्यस्थता अपने आप में अमान्य होगी। यह विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ होगा जिन्होंने संस्थागत नियमों के तहत दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया की वैधता को स्वीकार किया है और यह विचार नहीं लिया है कि दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया अपने आप में अमान्य है। द्विस्तरीय मध्यस्थता के सामान्य सिद्धांत की अंतर्निहित स्वीकृति में कोई त्रुटि नहीं है। [पैरा 34,35) [105-एफ-जी; 106-बी]

सतीश कुमार और अन्य बनाम सुरिंदर कुमार (1969) 2 एस. सी. आर. 244; उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी बनाम भारत संघ ने 1962 के सी. ए. सं. 162 पर निर्णय लिया; श्री लाल महल लिमिटेड बनाम प्रोजेटो ग्रानो स्पा (2014) 2 एस. सी. सी. 433; सुभाष अग्रवाल एजेंसियां बनाम भीलवाड़ा सिंथेटिक्स लिमिटेड (1994) पूरक। एस. सी. आर. 530: (1995) 1 एस. सी. सी. 371-संदर्भित।

एक मॉडल कानून के मसौदा पाठ पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी 011 सचिव-जेनेरा/अठारहवें सत्र, वियना का अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता-रिपोर्ट, 3-21 जून 1985, ए/सी. एन. 9/264 (25.03.1985); अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक/मध्यस्थता पर 1985 के मॉडल कानून पर UNCITRAL सचिवालय द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणी-संदर्भित

3. पार्टी की स्वायत्तता वस्तुतः मध्यस्थता की रीढ़ है। मध्यस्थता समझौते के पक्षकारों के पास न केवल प्रक्रिया संबंधी निर्णय लेने की स्वायत्तता होती है जिसका पालन किया जाना है, बल्कि मूल कानून भी होता है। अधिकार क्षेत्र का चुनाव अनुबंध करने वाले पक्षों पर छोड़ दिया गया है। तत्काल मामले में, पक्ष समझौते के खंड 14 के माध्यम से दो स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली पर सहमत हुए हैं और समझौते के खंड 16 में भारत के कानूनों के अनुसार किए गए अनुबंध के रूप में अनुबंध के निर्माण का प्रावधान है। दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत दोनों खंडों में से किसी में भी कुछ भी गलत नहीं है। [पैरा 36,40) [106-सी; 108-ई-एफ)

भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा निगम 2016 (1) एससीआर 364: (2016) 4 एससीसी 126; भारत संघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड (2015) 2 एससीसी 52-निर्दिष्ट

लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, निगेल ब्लैकबी, कॉन्स्टैंटाइन पार/एसाइड्स, एट अल।, रेडफर्न एंड हंटर (छठा संस्करण), (® क्लूवर लॉ इंटरनेशनल; ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2015) पीपी. 353-414; तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, जूलियन डी. एम. ल्यू, लुकास ए. मिस्टेलिस, और अन्य, (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल 2003) पीपी।

4.1 एसोसिएट बिल्डर्स के मामले में भारत की मौलिक नीति के व्यापक वर्णन को मानते हुए भी दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली को पसंद करने और स्वीकार करने

वाले पक्षों में मौलिक रूप से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। अनुबंध के पक्षों ने ए एंड सी अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान को पारित नहीं किया है और उन्हें पता था, या कम से कम उन्हें पता होना चाहिए था कि वे भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल द्वारा दिए गए निर्णय की अंतिमता पर सहमत हो सकते थे। फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से और जानबूझकर इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुलह और मध्यस्थता के नियमों के अनुसार लंदन, यूके में दूसरे या अपीलीय मध्यस्थता पर सहमत होने का फैसला किया। ए एंड सी अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनुबंध करने वाले पक्षों को दूसरे उदाहरण या अपीलीय मध्यस्थता पर सहमत होने से रोकता है-या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से। इस तरह के किसी भी निषेध या आदेश को ए एंड सी अधिनियम में पढ़ा नहीं जा सकता है, सिवाय एक अनुचित और अजीब गलत निर्माण के और इसकी भाषा को एक लुप्त होने वाले बिंदु तक दबाए जाने के। चिंता इस कारण से नहीं है कि पक्ष दूसरी बार मध्यस्थता के लिए सहमत क्यों हुए, तथ्य यह है कि उन्होंने ऐसा किया और वे उनके द्वारा किए गए समझौते से बाध्य हैं। एच. सी. एल. स्वेच्छा से, जानबूझकर और आंखें खुली रखते हुए अपने द्वारा की गई गंभीर प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट सकता है। (पैरा 441 1109-ई-जी; 110-ए-बीजे

एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 3 धारा 49-निर्दिष्ट। एमिकेबल सोसाइटी बनाम बोलैंड (फॉन्टलरॉय का मामला) (1830) 4 ब्लिघ। (एनएस) 194; 2 डाउ और सी. आई. 1-संदर्भित। इंग्लैंड, लंदन, बटरवर्थ्स, मस्टिल और बॉयड में वाणिज्यिक मध्यस्थता का कानून और अभ्यास 1982 पीपी।

4.2 पक्षकारों के बीच समझौते में मध्यस्थता खंड द्वितीय मध्यस्थता के लिए सहमत पक्षों द्वारा भारत की मौलिक या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता है।

यह इस प्रकार है कि जिस अवॉर्ड को एच. सी. एल. द्वारा चुनौती दी जानी आवश्यक है, वह लंदन में मध्यस्थ द्वारा दिया गया अवॉर्ड है। [पैरा 45] (110-सी]।

सेन्ट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल्स इंक. बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 2006 (2) सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 146: (2006) 11 एस. सी. सी. 245-संदर्भित।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2562/2006

साथ मे

सी.ए, 2006 का 2564

गौरव बनर्जी, सीनियर एड., प्रतीक जालान, आर. एन. करंजावाला, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, विशाल गेहराना, उत्सव त्रिवेदी, साहिल टागोत्रा, हर्ष त्रिवेदी, Ms.Videhi मिश्रा, अंकित यादव, श्रीमती माणिक करंजावाला, (मिस के लिए। करंजावाला एंड कंपनी), एस. एस. जौहर, अपीलार्थी के अधिवक्ता। प्रतिवादी की ओर से हरिन पी. रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री नंदिनी सेन, निपुण सक्सेना, आनंदो मुखर्जी, देब प्रसाद मुखर्जी, सुश्री दिव्या आनंद, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय मदन बी. लो कुर, जे. द्वारा दिया गया

I. इन अपीलों को इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद को देखते हुए तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया है। 9th मई, 2006 को दर्ज की गई कार्यवाही का उल्लेख करके विवाद को सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है।

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. सिन्हा ने उनके लॉर्डशिप और माननीय न्यायमूर्ति श्री तरुण चटर्जी की पीठ के अपने लॉर्डशिप के फैसले को सुनाया।

अनुमति प्रदान की गई।

हस्ताक्षरित निर्णय में उल्लिखित कारणों के लिए, मिस सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. द्वारा दायर एसएलपी (सी) No.1861112004 से उत्पन्न दीवानी अपील को खारिज कर दिया जाता है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा 2005 (वास्तव में 2004) के एसएलपी (सी) No.21340 से उत्पन्न दीवानी अपील की अनुमति दी जाती है। मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकार अपनी लागत का भुगतान करेंगे और वहन करेंगे।

माननीय न्यायमूर्ति श्री तरुण चटर्जी ने हस्ताक्षरित निर्णय के संदर्भ में अपीलों का निपटारा करते हुए अपने लॉर्डशिप के फैसले की घोषणा की।

मतभेद को देखते हुए, मामले को विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है। इस न्यायालय की रजिस्ट्री इस मामले को एक बड़ी पीठ के गठन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेगी।

न्यायमूर्ति सिन्हा और न्यायमूर्ति चटर्जी द्वारा लिए गए निर्णयों को सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल्स इंक बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

2. चूँकि मामले के तथ्यों को दोनों विद्वान न्यायाधीशों द्वारा अपने अलग-अलग निर्णयों में विस्तृत किया गया है, इसलिए हमारे लिए तीसरी बार उनका विस्तार करना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, यह बताना आवश्यक है कि दोनों पक्षों ने एक अनुबंध किया था और उनके बीच कुछ विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए थे। अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड था और सेंट्रोट्रेड ने इसे लागू किया। इसके अनुसार भारतीय मध्यस्थता परिषद ने एक मध्यस्थ नियुक्त किया। मध्यस्थ ने एक एन. आई. एल. अवॉर्ड दिया और फिर सेंट्रोट्रेड ने मध्यस्थता खंड के दूसरे भाग को लागू किया और लंदन में मध्यस्थ ने 291 एच. सितंबर, 200 । को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के सुलह और मध्यस्थता के नियमों

के अनुसार एक अवॉर्ड दिया। लंदन में मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 48 के तहत एक आवेदन दायर करके केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू करने की मांग की गई थी

3. पक्षों के बीच अनुबंध में मध्यस्थता खंड खंड 14 है और यह इस प्रकार हैः

"14. मध्यस्थता अनुबंध के निर्माण, अर्थ और संचालन या प्रभाव या उसके उल्लंघन से संबंधित या उससे संबंधित पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवाद या मतभेद भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल के माध्यम से भारत में मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाएंगे।

यदि कोई भी पक्ष भारत में मध्यस्थता के परिणाम से असहमत है, तो किसी भी पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के सुलह और मध्यस्थता के नियमों के अनुसार लंदन, यू. के. में दूसरे मध्यस्थता के लिए अपील करने का अधिकार होगा और इस दूसरे मध्यस्थता का परिणाम दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। अवॉर्ड पर निर्णय अधिकार क्षेत्र में किसी भी अदालत में दर्ज किया जा सकता है।

4. अनुबंध का खंड 16 भी महत्वपूर्ण है और यह इस प्रकार हैः

"16 निर्माण-अनुबंध का निर्माण किया जाना है और भारत के कानूनों के अनुसार किए गए अनुबंध के रूप में प्रभावी होना है।

5. विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद के परिणामस्वरूप हमारे विचार के लिए जो मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, वे इस प्रकार हैंः

(I) क्या पक्षों के बीच अनुबंध के खंड 14 में प्रदान की गई दो स्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से विवादों या मतभेदों का निपटान भारत के कानूनों के तहत अनुमत है?

(2) यह मानते हुए कि भारत के कानूनों के तहत दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया की अनुमति है, क्या अपीलीय मध्यस्थता में दिया गया अवॉर्ड एक 'विदेशी पुरस्कार' होने के नाते मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 48 के प्रावधानों के तहत लागू होने के लिए उत्तरदायी है? यदि ऐसा है, तो सेंट्रोट्रेड किस राहत का हकदार है?

वर्तमान में, हम केवल पहले प्रश्न को संबोधित करने का प्रस्ताव करते हैं और उत्तर के आधार पर, अपीलों को शेष मुद्दे पर सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाएगा। हमने यह कुछ असामान्य तरीका अपनाया है क्योंकि कार्य सूची ने हमें केवल छिटपुट रूप से अपीलों की सुनवाई करने की अनुमति दी और इसलिए हमारे सामने की कार्यवाही लगभग तीन महीने तक चली।

अनुबंध के खंड 14 की सराहना करना

6. शुरू में, अनुबंध में मध्यस्थता खंड पर सहमत होने पर पक्षों के इरादे की सराहना करना आवश्यक है। मध्यस्थता खंड के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि अनुबंध करने वाले पक्षों का इरादा थाः (ए) सबसे पहले, भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल के माध्यम से और भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार भारत में मध्यस्थता द्वारा अपने विवादों या मतभेदों का निपटारा, और (बी) दूसरा, यदि अनुबंध करने वाले पक्षों में से कोई भी भारत में 'मध्यस्थता परिणाम' से असहमत था, तो पीड़ित पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के सुलह और मध्यस्थता नियमों के अनुसार लंदन में दूसरे मध्यस्थता के लिए अपील करने का अधिकार होगा। अपीलीय मध्यस्थता का परिणाम कानून के अनुसार कानूनी चुनौती के

अधीन दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता खंड का पाठ काफी स्पष्ट और स्पष्ट है और इसकी व्याख्या पर किसी भी संदेह को स्वीकार नहीं करता है। अनुबंध करने वाले पक्षों का इरादा अनुबंध के खंड 14 में अपने विवादों या मतभेदों को हल करने के लिए दो अवसर प्रदान करना था। पहला अवसर भारत में मध्यस्थता द्वारा समझौता ('मध्यस्थता परिणाम') होगा और दूसरा अवसर लंदन में मध्यस्थता द्वारा होगा, दूसरा अवसर भारत में 'मध्यस्थता परिणाम' के खिलाफ अपील की प्रकृति में होगा।

7. सेंट्रोट्रेड के विद्वान वकील का यह तर्क था कि भारत में 'मध्यस्थता परिणाम' एक ऐसा निर्णय नहीं था जिसे पारंपरिक रूप से मध्यस्थता के संदर्भ में समझा जाता है, बल्कि केवल 'भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल द्वारा दिए गए मध्यस्थता का परिणाम था और इससे अधिक कुछ नहीं। हम इस व्याख्या को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। जबकि अनुबंध के खंड 14 ने 'मध्यस्थता परिणाम' अभिव्यक्ति का उपयोग किया होगा न कि 'मध्यस्थता पुरस्कार' अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप से पक्षों का इरादा था कि 'मध्यस्थता परिणाम' एक अवॉर्ड होगा या कम से कम भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल द्वारा दिए गए अवॉर्ड की प्रकृति में होगा। मध्यस्थता समिति के समक्ष कार्यवाही का उद्देश्य भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार संरचित और आयोजित किया जाना था। इस तरह की कार्यवाही का परिणाम अनिवार्य रूप से एक मध्यस्थता अवॉर्ड होगा, चाहे पक्षकारों द्वारा उपयोग किए गए नामकरण की परवाह किए बिना। मध्यस्थता अवॉर्ड के अर्थ के अलावा 'मध्यस्थता परिणाम' शब्दों की व्याख्या करना मुश्किल है।

8. हम ऐसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यदि सेंट्रोट्रेड के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति को स्वीकार किया जाना था, तो इसका मतलब यह होगा कि यदि दोनों अनुबंधित पक्ष 'मध्यस्थता परिणाम' से संतुष्ट थे (या नकारात्मक रूप से कहें तो, यदि

कोई भी पक्ष 'मध्यस्थता परिणाम' से असंतुष्ट नहीं था) तो उस 'मध्यस्थता परिणाम' को लागू करने का कोई तरीका नहीं होगा यदि ऐसा प्रवर्तन आवश्यक हो जाए। यह 'मध्यस्थता परिणाम' के बाद एक निर्वात पैदा करेगा। यह इस तरह की कमी से बचने के लिए है कि 'मध्यस्थता परिणाम' का अर्थ भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल का एक अवॉर्ड और एक ऐसा अवॉर्ड है जिसे भारत के कानूनों, यानी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, । 996 (संक्षेप में 'ए एंड सी अधिनियम') के अनुसार लागू किया जा सकता है।

9. जिस सामान्य सिद्धांत को हमने स्वीकार किया है, वह तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अंशों द्वारा समर्थित है। पैराग्राफ 24-3 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून (या UNCITRAL) नियमों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अनुच्छेद 31 (।) का संदर्भ दिया गया है ताकि यह सुझाव दिया जा सके कि सभी अवॉर्ड मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय हैं, लेकिन मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सभी निर्णय अवॉर्ड नहीं हैं। इसी तरह, जबकि एक निर्णय सामान्य है, एक अवॉर्ड एक अधिक विशिष्ट निर्णय है जो पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करता है, इसके महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं और इसे लागू किया जा सकता है। एक अवॉर्ड और एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के बीच के अंतर को पैराग्राफ 24-13 में संक्षेपित किया गया है। यह देखा जाता है कि एक पुरस्कारः

(i) पंचाट में निर्धारित विशिष्ट मुद्दे के बारे में विवाद को समाप्त करता है ताकि इसका पक्षों के बीच न्यायिक प्रभाव हो; यदि यह अंतिम पंचाट है, तो यह न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर देता है;

((ख) पक्षकारों के संबंधित दावों का निपटान करता है।

(iii) मान्यता और प्रवर्तन द्वारा पुष्टि की जा सकती है;

(iv) मध्यस्थता के स्थान की अदालतों में चुनौती दी जा सकती है।

10. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में एक अवॉर्ड और प्रक्रियात्मक आदेशों और निर्देशों जैसे निर्णयों के बीच एक समान अंतर किया जाता है। यह देखा गया है कि एक अवॉर्ड में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय के साथ अंतिमता जुड़ी होती है। इस संदर्भ में पैराग्राफ 9.08 इस प्रकार हैः

> "9.08 'पुरस्कार' शब्द आम तौर पर उन निर्णयों के लिए आरक्षित होना चाहिए जो अंततः उन मूल मुद्दों को निर्धारित करते हैं जिनसे वे निपटते हैं। इसमें उन पुरस्कारों के बीच अंतर करना शामिल है, जो मूल मुद्दों से संबंधित हैं, और प्रक्रियात्मक आदेश और निर्देश, जो मध्यस्थता के संचालन से संबंधित हैं। प्रक्रियात्मक आदेश और निर्देश मध्यस्थता को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं; वे लिखित साक्ष्य के आदान-प्रदान, दस्तावेजों के उत्पादन और सुनवाई के संचालन की व्यवस्था जैसे मामलों से निपटते हैं। उनके पास पुरस्कारों का दर्जा नहीं है और अंतिम अवॉर्ड दिए जाने के बाद शायद उन पर सवाल उठाए जा सकते हैं (उदाहरण के लिए 'पक्षपात' या 'उचित प्रक्रिया की कमी' के प्रमाण के रूप में)।

11. अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एक अवॉर्ड की सामान्य विशेषताओं को बताया गया है।

पैराग्राफ 1353 में यह इस प्रकार कहा गया हैः 1353.-एक मध्यस्थता अवॉर्ड को मध्यस्थों द्वारा उन्हें प्रस्तुत किए गए विवाद के सभी या भाग पर अंतिम निर्णय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, चाहे वह विवाद, अधिकार क्षेत्र, या एक प्रक्रियात्मक

मुद्दे के गुण-दोष से संबंधित हो जो उन्हें कार्यवाही समाप्त करने के लिए प्रेरित करता हो।

यह बाद में एक अवॉर्ड के चार पहलुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है, अर्थात्ः (i) मध्यस्थों द्वारा एक अवॉर्ड दिया जाता है; (ii) एक अवॉर्ड एक विवाद का समाधान करता है; (iii) एक अवॉर्ड एक बाध्यकारी निर्णय है; और (iv) एक अवॉर्ड आंशिक हो सकता है।

12. वर्तमान मामले में मध्यस्थता परिणाम में मध्यस्थता निर्णय के सभी तत्व और तत्व हैं। उपरोक्त लेखकों द्वारा व्यक्त विचार को भी ध्यान में रखते हुए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि अनुबंध के खंड 14 के पहले भाग में 'मध्यस्थता परिणाम' का अर्थ भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थ पैनल द्वारा दिया गया मध्यस्थता अवॉर्ड होना चाहिए। इस हद तक हम सेंट्रोट्रेड के विद्वान वकील से असहमत हैं लेकिन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (जिसे बाद में 'एचसीएल' के रूप में संदर्भित किया गया है) के विद्वान वकील से सहमत हैं।

13. सेन्ट्रोट्रेड के लिए विद्वान वकील का वैकल्पिक निवेदन यह है कि किसी भी स्थिति में मध्यस्थता परिणाम से असंतुष्ट होने पर, समझौते के खंड 14 का दूसरा भाग पीड़ित पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के सुलह और मध्यस्थता के नियमों के अनुसार लंदन में दूसरे मध्यस्थता के लिए अपील करने का अधिकार देता है। हालांकि, एच. सी. एल. के विद्वान वकील के अनुसार अनुबंध के खंड 14 का दूसरा भाग भारत के कानूनों के विपरीत है।

14. हमारी राय में खंड 14 की सरल भाषा विशेष रूप से भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल के निर्णय के खिलाफ 'अपील' के रूप में दूसरे मध्यस्थता का प्रावधान करती है। खंड 14 में उपयोग किए गए स्पष्ट शब्दों को देखते हुए हम इस

मुद्दे पर काम करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। रिकॉर्ड के लिए, हम ध्यान दे सकते हैं कि एच. सी. एल. के विद्वान वकील ने यह समझाने में काफी समय बिताया कि अपील दायर करने का अधिकार केवल एक क़ानून द्वारा बनाया जा सकता है न कि पक्षों के बीच एक समझौते द्वारा। यह किसी कानून के तहत अदालतों में शुरू किए गए मुकदमे के संबंध में या सामान्य कानून अधिकारों को लागू करने के संबंध में हो सकता है, लेकिन यह पक्षों को गैर-वैधानिक अपीलों के लिए एक समझौते में प्रवेश करने से नहीं रोकता है ताकि उनके विवादों और मतभेदों को अदालत की प्रक्रियाओं का सहारा लिए बिना हल किया जा सके।

15. हालांकि, जिस पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है, वह है एचसीएल के लिए नामित वकील का यह निवेदन कि खंड 14 में अपीलीय मध्यस्थता का प्रावधान भारत के कानूनों द्वारा तीन मामलों में निषिद्ध हैः ए एंड सी अधिनियम के प्रावधान एक अपीलीय मध्यस्थता को मंजूरी नहीं देते हैं; ए एंड सी अधिनियम में एक अपीलीय मध्यस्थता के लिए एक निहित निषेध है; और एक अपीलीय मध्यस्थता अन्यथा सार्वजनिक नीति के विपरीत भी है।

अपीलीय मध्यस्थता और ए एंड सी अधिनियम

16. ए एंड सी अधिनियम के संदर्भ में एक अपीलीय मध्यस्थता की वैधता पर वास्तव में चर्चा करने से पहले, यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह संदिग्ध है कि क्या एचसीएल यह भी तर्क दे सकता है कि एक अपीलीय मध्यस्थता भारत के कानूनों के विपरीत है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह तर्क दिया जा सकता है कि एच. सी. एल. ने सेंट्रोट्रेड के साथ एक अनुबंध किया था जो पूरी तरह से सचेत और जागरूक था कि अनुबंध के प्रावधानों में से एक भारत के कानूनों के विपरीत था। यह एच. सी. एल. द्वारा सेंट्रोट्रेड पर धोखाधड़ी करने के बराबर हो सकता है और

इसके भारतीय पक्ष के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुबंधों के लिए गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव और प्रभाव हो सकते हैं।

17. लेकिन जो भी हो, अपने तीसरे सत्र के कार्य पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध प्रथाओं पर कार्य समूह की रिपोर्ट में व्यक्त विचार पर विचार करना एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोगी हो सकता है। संयोग से, भारत उस UNCITRAL कार्य समूह के राज्य सदस्यों में से एक था। एक मध्यस्थता अवॉर्ड के खिलाफ एक अपील [एक अन्य मध्यस्थता न्यायाधिकरण (दूसरी बार) के समक्ष] के संदर्भ में, प्रश्न 6-1 प्रस्तुत किया गया और इसका उत्तर इस प्रकार दिया गयाः

> "प्रश्न 6-1: क्या आदर्श कानून को पक्षों द्वारा किसी भी समझौते को मान्यता देनी चाहिए कि मध्यस्थता निर्णय को किसी अन्य मध्यस्थता न्यायाधिकरण (दूसरी बार) के समक्ष अपील की जा सकती है?
>
> 106. इस विचार के लिए व्यापक समर्थन था कि पक्ष इस बात पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र थे कि अवॉर्ड को किसी अन्य मध्यस्थता न्यायाधिकरण (दूसरी बार) के समक्ष अपील की जा सकती है, और यह कि मॉडल कानून को इस तरह की प्रथा को बाहर नहीं करना चाहिए, हालांकि इसका उपयोग सभी देशों में नहीं किया गया था। हालांकि, कार्य समूह इस बात पर सहमत था कि इस तरह की प्रथा को मान्यता देने वाले प्रावधान को मॉडल कानून में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यह नोट किया गया था कि इस निष्कर्ष पर मॉडल कानून की अंतिम सामग्री और विशेष रूप से एक अवॉर्ड के खिलाफ सहारा लेने के साधनों पर इसके अध्याय के

आलोक में पुनर्विचार करना पड़ सकता है। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

यह दृष्टिकोण पार्टी की स्वायत्तता के मुद्दे को भी खोलता है, जिसका हम थोड़ी देर बाद प्रचार करेंगे। लेकिन वर्तमान में, हम मध्यस्थता व्यवहार की पुस्तिका का भी उल्लेख कर सकते हैं जिसमें मध्यस्थता की दो-स्तरीय प्रणाली का संदर्भ दिया गया है, विशेष रूप से वस्तु व्यापार में निम्नलिखित शब्दों में:

" ..... जिंस व्यापार मध्यस्थता की मौलिक और प्राचीन विशेषता दो स्तरीय प्रणाली है जिसके तहत पहला मध्यस्थता तेजी से और अपेक्षाकृत अनौपचारिक रूप से आयोजित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप एक अवॉर्ड जारी किया जाता है, जिसे समय सीमा के अधीन, एक असंतुष्ट पक्ष द्वारा संबंधित संघ के अपील बोर्ड में अपील की जा सकती है। यह एक पक्ष को चेरी पर दो काटने देता है और मध्यस्थता प्रक्रिया को तब तक समाप्त नहीं माना जाता है जब तक कि अपील बोर्ड अपना अंतिम निर्णय जारी नहीं कर देता है। दो स्तरीय प्रणालियों में, न्यायाधिकरण, एकमात्र मध्यस्थ या अंपायर के पुरस्कारों को आमतौर पर मध्यस्थता के अवॉर्ड कहा जाता है; उन्हें अपील बोर्ड द्वारा जारी अपील पुरस्कारों से अलग करने के लिए।

18. हमारा ध्यान कई ऐसे क्षेत्राधिकारों की ओर भी आकर्षित किया गया है जिनमें मध्यस्थता की दो-स्तरीय प्रणाली की वैधानिक स्वीकृति प्रचलित है, लेकिन इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एचसीएल के विद्वान वकील का तर्क है कि ए एंड सी अधिनियम के माध्यम से भारत में कानून काफी अलग है।

19. पक्षों के विद्वान वकील इस बात से सहमत हैं कि ऐतिहासिक रूप से भारत में ए एंड सी अधिनियम के अधिनियमन से पहले, दो-स्तरीय मध्यस्थता की अनुमति थी। न्यायमूर्ति सिन्हा ने ए एंड सी अधिनियम से पहले भारत में दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली के अस्तित्व की ओर इशारा किया और इस संबंध में कई फैसलों का उल्लेख किया, लेकिन इसकी वैधता या अन्यथा पर निर्णय नहीं दिया। हालांकि, न्यायमूर्ति चटर्जी की राय थी कि ए एंड सी अधिनियम से पहले भारत में दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली वैध और अनुमेय थी

20. इसका महत्व यह है कि यह माना जाना चाहिए कि संसद को यू. एन. सी. एल. टी. आर. ए. एल. कार्य समूह (जिसमें भारत एक राज्य सदस्य था) के दृष्टिकोण की जानकारी थी और यह माना जाना चाहिए कि वह विभिन्न घरेलू न्यायालयों के निर्णयों को जानती थी और फिर भी उसने विशेष रूप से दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली को प्रतिबंधित नहीं करने का फैसला किया। यदि ऐसा है, तो हम इस आधार पर आगे बढ़ने के हकदार हैं कि ए एंड सी अधिनियम के पारित होने के बाद भी, शायद दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली के अस्तित्व पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन हम इस धारणा के आधार पर अपने निर्णय का प्रस्ताव नहीं करते हैं। हालाँकि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णय हैं जिन्होंने दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली को स्वीकार किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं जिन्होंने यह विचार रखा है कि चूंकि ए एंड सी अधिनियम दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया को प्रतिबंधित नहीं करता है, इसलिए ऐसी प्रणाली स्वीकार्य है

21. एच. सी. एल. के विद्वान वकील ने फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 11 के निम्नलिखित अंश पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि चूंकि

ए एंड सी अधिनियम दो-स्तरीय मध्यस्थता की अनुमति नहीं देता है, इसलिए ऐसी मध्यस्थता प्रणाली की अनुमति नहीं थीः

> "89. इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को अपनी स्थापना से लेकर 2004 तक (पी. एस. सतप्पन 11 में) एक स्व-निहित संहिता माना गया था। अब, यदि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को मध्यस्थता से संबंधित मामलों पर एक स्व-निहित संहिता माना गया था, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, जो इसे लाने के लिए मध्यस्थता से संबंधित कानून को समेकित करता है, संशोधन करता है और डिजाइन करता है, जितना संभव हो सके, UNCITRAL मॉडल के अनुरूप होना चाहिए। एक बार जब यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता और संपूर्ण है, तो न्यायमूर्ति तुलजापुरकर की स्पष्ट अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए यह भी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि यह इसके साथ एक नकारात्मक महत्व रखता है कि केवल ऐसे कार्य जो अधिनियम में उल्लिखित हैं, किए जाने की अनुमति है और जिन कार्यों या चीजों का उसमें उल्लेख नहीं है, उन्हें करने की अनुमति नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक पत्र पेटेंट अपील को सामान्य सिद्धांतों में से एक के आवेदन द्वारा बाहर रखा जाएगा कि जहां विशेष अधिनियम एक स्व-निहित संहिता निर्धारित करता है, वहां सामान्य कानून प्रक्रिया की प्रयोज्यता को निहित रूप से बाहर रखा जाएगा।

22. दूसरी ओर, आई. टी. आई. लिमिटेड बनाम सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशंस नेटवर्क लिमिटेड मामले में इस अदालत के समक्ष सवाल यह था कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान ए एंड सी अधिनियम पर लागू होते हैं या नहीं। जवाब में,

इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि ए एंड सी अधिनियम में संहिता के प्रावधानों को छोड़कर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, इसलिए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि संहिता के प्रावधान लागू नहीं थे।

23. किसी भी स्थिति में, हमें डर है कि फ़्यूर्स्ट डे लॉसन के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित मार्ग को गलत समझा गया है और यह अन्यथा भी अनुचित है क्योंकि हम एक सांविधिक अपील से संबंधित नहीं हैं, बल्कि एक गैर-सांविधिक प्रक्रिया है जिस पर पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है जिसका अदालत की प्रक्रियाओं से कोई लेना-देना नहीं है। हम इस व्यापक अवलोकन को पूरी तरह से स्वीकार करने में भी असमर्थ हैं कि किसी क़ानून में उल्लिखित कार्य अनुमत हैं लेकिन उनमें उल्लिखित कार्य अस्वीकार्य हैं। यह बहुत अच्छी तरह से विपरीत हो सकता है। किसी भी स्थिति में, इस न्यायालय की टिप्पणियां एक वैधानिक अपील के संदर्भ में थीं जो प्रदान नहीं की गई थीं (या प्रदान की गई थीं)। उस संदर्भ में, यह देखा गया कि यदि किसी कानून द्वारा अपील का प्रावधान नहीं है, तो अपील दायर करने की अनुमति नहीं है। यह कई साल पहले गरिकापति वीराया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी मामले में संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट किया गया था जब यह निष्कर्ष निकाला गया था कि-

> "ऊपर बताए गए निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट रूप से सामने आते हैंः (i) यह कि किसी उपचार, वाद, अपील और दूसरी अपील की कानूनी खोज वास्तव में एक आंतरिक एकता से जुड़ी कार्यवाहियों की एक श्रृंखला में कदम हैं और इन्हें एक कानूनी कार्यवाही के रूप में माना जाना चाहिए।
>
> (ii) अपील का अधिकार केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है।

(iii) वाद की संस्था अपने साथ यह निहितार्थ रखती है कि तब लागू अपील के सभी अधिकार पक्षकारों को मुकदमे के शेष कार्यकाल तक संरक्षित किए जाते हैं।

(iv) अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है और उच्च न्यायालय में प्रवेश करने का ऐसा अधिकार वादी को प्राप्त होता है और शुरू होने की तारीख से ही मौजूद होता है और हालांकि इसका वास्तव में प्रयोग प्रतिकूल निर्णय के समय किया जा सकता है। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

हम ए एंड सी अधिनियम द्वारा प्रदान नहीं की गई अपील से संबंधित नहीं हैं, बल्कि अनुबंध के पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत एक अपील प्रक्रिया से संबंधित हैं। यह पक्ष की स्वायत्तता का एक क्षेत्र है, जिस पर हम थोड़ी देर बाद विचार करेंगे, लेकिन वर्तमान के लिए अगला मुद्दा यह है कि क्या ए एंड सी अधिनियम आवश्यक निहितार्थ से दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली को प्रतिबंधित करता है।

24. एचसीएल के विद्वान वकील द्वारा पहले धारा 34 की उप-धारा (1) के प्रावधानों और फिर ए एंड सी अधिनियम की धारा 35 और 36 का संदर्भ दिया गया था। इन्हें इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

"34. माध्यस्थम् अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन-(I) माध्यस्थम् अधिनिर्णय के विरुद्ध न्यायालय का सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन द्वारा लिया जा सकता है।

35. इस भाग के लिए मध्यस्थता की अंतिमता एक मध्यस्थता अवॉर्ड अंतिम होगा और उनके तहत दावा करने वाले पक्षों और व्यक्तियों पर क्रमशः बाध्यकारी होगा।

36. प्रवर्तन. (1) जहां धारा 34 के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड को रद्द करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, तो, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसा अवॉर्ड सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से लागू किया जाएगा जैसे कि यह अदालत की डिक्री थी।

(2) जहां धारा 34 के तहत न्यायालय में मध्यस्थता अवॉर्ड को रद्द करने का आवेदन दायर किया गया है, वहां ऐसा आवेदन दायर करने से स्वयं उस अवॉर्ड को अप्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता है, जब तक कि न्यायालय उस उद्देश्य के लिए किए गए एक अलग आवेदन पर, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार उक्त मध्यस्थता अवॉर्ड के संचालन पर रोक लगाने का आदेश नहीं देता है।

(3) माध्यस्थम अधिनिर्णय के संचालन पर रोक लगाने के लिए उप-धारा (2) के तहत आवेदन दायर करने पर, न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे अवॉर्ड के संचालन पर रोक लगा सकता हैः बशर्ते कि xxx xxx xxx"

25. हम इस बात की सराहना करने में असमर्थ हैं कि ये प्रावधान एचसीएल के विद्वान वकील की सहायता के लिए कैसे आते हैं। ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) मध्यस्थता के लिए एक पक्ष को एक अवॉर्ड को रद्द करने के लिए

"केवल एक आवेदन द्वारा" अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देती है। विद्वान वकील द्वारा इसे एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश की जाती है ताकि यह सुझाव दिया जा सके कि एक अवॉर्ड को केवल एक अदालत द्वारा अलग किया जा सकता है, जिससे दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया को बाहर रखा जा सकता है। यदि विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार किया जाना है, तो हमें "केवल" शब्द को प्रतिस्थापित करके उप-धारा को काफी अलग तरीके से पढ़ना होगा और उप-धारा को पढ़ने के लिएः "उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे अवॉर्ड को रद्द करने के लिए आवेदन द्वारा केवल मध्यस्थता अवॉर्ड के खिलाफ न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है।" या "माध्यस्थम अधिनिर्णय के विरुद्ध सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए एक आवेदन द्वारा किसी न्यायालय को दिया जा सकता है।" हमें डर है कि हम विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए तरीके से क़ानून को पढ़ या फिर से तैयार नहीं कर सकते हैं।

26. विद्वान वकील चाहेंगे कि हम ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (I) को उसकी धारा 35 के संयोजन के साथ पढ़ें और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालें कि एक मध्यस्थता अवॉर्ड अंतिम और बाध्यकारी होगा जब तक कि इसे अदालत द्वारा चुनौती नहीं दी जाती है और अलग नहीं किया जाता है और यह कि अलग करना केवल अदालत द्वारा हो सकता है और कोई और नहीं। इस निवेदन की स्वीकृति तभी संभव होगी जब हम ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (I) के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई व्याख्या को पहले स्वीकार करें। हालाँकि, चूंकि हम ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) की व्याख्या पर विद्वान वकील से सहमत नहीं हैं, इसलिए पक्षपाती वकील के तर्क की स्वीकृति उत्पन्न नहीं होती है।

27. हमारी राय में, ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) और उसकी धारा 35 के संयुक्त अध्ययन पर, एक मध्यस्थता अवॉर्ड अंतिम और पक्षों के

लिए बाध्यकारी होगा जब तक कि इसे मध्यस्थता अवॉर्ड के लिए एक पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर एक सक्षम अदालत द्वारा अलग नहीं किया जाता है। यह एक प्रक्रिया के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होने के लिए एक मध्यस्थता अवॉर्ड के लिए पक्षों की स्वायत्तता को बाहर नहीं करता है जिसके द्वारा मध्यस्थता अवॉर्ड पर किसी अन्य मध्यस्थ या मध्यस्थों के पैनल द्वारा अपील के माध्यम से पुनर्विचार किया जा सकता है और उस अपील के परिणाम को पक्षकारों द्वारा अंतिम और ए एंड सी अधिनियम द्वारा प्रदान की गई चुनौती के अधीन बाध्यकारी होने के लिए स्वीकार किया जाता है। वास्तव में दोनों पक्ष इसी पर सहमत हुए हैं और हम उनके आपसी निर्णय का सम्मान करने और उनके समझौते की वैधता को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं देखते हैं।

28. यह तथ्य कि किसी निर्णय को चुनौती देने के लिए किसी पक्ष के लिए अदालत का सहारा उपलब्ध है, वास्तव में पक्षों को विवादों और मतभेदों के शीघ्र निपटारे के इरादे से किसी निर्णय पर पारस्परिक रूप से सहमत होने से नहीं रोकता है। ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समुदाय का इरादा एक पक्ष को कई मंचों पर एक अवॉर्ड को चुनौती देने के लिए एक मध्यस्थता समझौते के अधीन करने से बचना है, जैसे कि एक दीवानी अदालत में कार्यवाही के साथ-साथ मध्यस्थता क़ानून के तहत। इसका उद्देश्य पक्षों की स्वायत्तता को कम करना या उन्हें अपीलीय मध्यस्थता जैसे निवारण के किसी अन्य स्वीकार्य तरीके को अपनाने से रोकना नहीं है। इस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर एक मॉडल कानून के मसौदा पाठ पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी में व्यक्त किया गया विचार-महासचिव की रिपोर्ट काफी प्रासंगिक है। यह टिप्पणी, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता 17 पर आदर्श कानून के अनुच्छेद 34 (1) से संबंधित है और इसे इस प्रकार कहा गया हैः

"1.मौजूदा राष्ट्रीय कानून किसी पक्ष को अवॉर्ड पर हमला करने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्रवाई या उपचार प्रदान करते हैं। अक्सर स्थानीय अदालत के फैसलों के साथ मध्यस्थता पुरस्कारों की तुलना करते हुए, वे विभिन्न और कभी-कभी बेहद लंबी अवधि निर्धारित करते हैं और विभिन्न और कभी-कभी उन आधारों की लंबी सूची निर्धारित करते हैं जिन पर अवॉर्ड पर हमला किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 काफी कम समय के दौरान और सीमित संख्या में कारणों के लिए उपलब्ध आश्रय का केवल एक साधन प्रदान करके इस स्थिति को सुधारने के लिए बनाया गया है।

2. खारिज करने के लिए आवेदन इस अर्थ में अवॉर्ड के खिलाफ अदालत का विशेष सहारा है कि यह अवॉर्ड पर सक्रिय रूप से हमला करने का एकमात्र साधन है, यानी न्यायिक समीक्षा के लिए कार्यवाही शुरू करना। अंत में, अनुच्छेद 34 (1) दूसरे मध्यस्थता न्यायाधिकरण का सहारा लेने से बाहर नहीं करेगा, जहां मध्यस्थता प्रणाली के भीतर ऐसी अपील की परिकल्पना की गई है (जैसे, कुछ वस्तु व्यापारों में)। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]

29. इसी तरह, 2006 में संशोधित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर 1985 के मॉडल कानून पर UNCITRAL सचिवालय द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणी भी निम्नलिखित शब्दों में इस स्थिति की पुष्टि करती है।

44. राष्ट्रीय कानूनों में पक्षकारों के लिए उपलब्ध मध्यस्थता निर्णय के खिलाफ सहायता के प्रकारों के संबंध में पाई जाने वाली असमानता अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कानून के सामंजस्य में एक बड़ी कठिनाई

प्रस्तुत करती है। मध्यस्थता पर कुछ पुराने कानून, मध्यस्थता पुरस्कारों के खिलाफ या अदालत के फैसलों के खिलाफ सहारा लेने के लिए समानांतर शासन स्थापित करके, विभिन्न प्रकार के सहारा, सहारा लेने के लिए विभिन्न (और अक्सर लंबी) समय-अवधि और आधारों की व्यापक सूची प्रदान करते हैं जिन पर सहारा लिया जा सकता है। उस स्थिति (अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में शामिल लोगों के लिए काफी चिंता का विषय) में मॉडल कानून द्वारा बहुत सुधार किया गया है, जो एक समान आधार प्रदान करता है जिस पर (और स्पष्ट समय अवधि जिसके भीतर) मध्यस्थता अवॉर्ड के खिलाफ सहारा लिया जा सकता है।

ए. विशेष उपाय के रूप में अलग रखने के लिए आवेदन

45. सुधार का पहला उपाय राज्य के किसी भी प्रक्रियात्मक कानून में विनियमित किसी भी अन्य उपाय के बहिष्कार के लिए केवल एक प्रकार के उपाय की अनुमति देना है। अनुच्छेद 34 (1) में प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थता अवॉर्ड के खिलाफ एकमात्र उपाय अलग करने के लिए आवेदन करना है, जो अवॉर्ड प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए (अनुच्छेद 34 (3))। "उपाय" को विनियमित करने में (अर्थात, वह साधन जिसके माध्यम से कोई पक्ष सक्रिय रूप से अवॉर्ड पर "हमला" कर सकता है), अनुच्छेद 34 किसी पक्ष को प्रवर्तन कार्यवाही में बचाव के माध्यम से अदालत के नियंत्रण की मांग करने से नहीं रोकता है (अनुच्छेद 35 और 36)। अनुच्छेद 34 न्यायालय के समक्ष कार्रवाई तक सीमित है (अर्थात, किसी राज्य की न्यायिक प्रणाली का एक अंग)। हालांकि; एक पक्ष को दूसरी बार

मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अपील करने से नहीं रोका जाता है यदि पक्षकार ऐसी संभावना पर सहमत हो गए हैं (जैसा कि कुछ वस्तु व्यापारों में आम है)। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

30. एच. सी. एल. के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि पहली बार का अवॉर्ड अंतिम है और ए एंड सी अधिनियम की धारा 35 के तहत पक्षों पर बाध्यकारी है, इसलिए अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच समझौते में 'अपील' का प्रावधान नहीं हो सकता है। मध्यस्थता अवॉर्ड की "अंतिम और बाध्यकारी" प्रकृति (ए एंड सी अधिनियम की धारा 35 द्वारा अभिनिर्धारित) इस न्यायालय में विचार के लिए सामने आई है। इस न्यायालय ने यह विचार रखा है कि एक अवॉर्ड केवल इसलिए अपव्यय पत्र नहीं है क्योंकि इसे लागू नहीं किया गया है। अवॉर्ड के अस्तित्व के कुछ कानूनी परिणाम भी होते हैं। सतीश कुमार और अन्य बनाम सुरिंदर कुमार में मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की अनुसूची । के अनुच्छेद 7 पर विचार किया गया था। यह ए एंड सी अधिनियम की धारा 35 के लगभग समान है। इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न थाः क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत एक निजी संदर्भ पर दिए गए निर्णय के लिए भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा ।7 (1) (b) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होती है, यदि यह निर्णय अचल संपत्ति के विभाजन को प्रभावित करता है जो Rs.100 के मूल्य से अधिक है?

31. उस मामले में, इस न्यायालय ने उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी बनाम भारत संघ के निम्नलिखित अंश पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि एक बार किसी विषय-वस्तु पर निर्णय दिए जाने के बाद, मूल दावे पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है जो संदर्भ का विषय था। यह न्यायालय एक 'अपील' प्रक्रिया के माध्यम से आगे की जांच के लिए अवॉर्ड की शुद्धता के विषय में पक्षों के बीच किसी भी समझौते से संबंधित नहीं था। यह आयोजित किया गया थाः

"अवॉर्ड के प्रभाव के संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति विवाद में नहीं है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक सामान्य नियम के रूप में, सभी दावे जो मध्यस्थता के संदर्भ का विषय हैं, उस निर्णय में विलय हो जाते हैं जो मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में सुनाया जाता है और यह कि एक अवॉर्ड घोषित होने के बाद, उक्त दावों के संबंध में पक्षों के अधिकार और देनदारियों का निर्धारण केवल उक्त निर्णय के आधार पर किया जा सकता है। अवॉर्ड घोषित होने के बाद, मूल दावे पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है जो संदर्भ का विषय था। जैसा कि न्यायमूर्ति मुखर्जी ने भजहारी साहा बनिक्या बनाम बिहारी लाल बसाक के मामले में कहा है, "यह अवॉर्ड वास्तव में पक्षकारों की अपनी पसंद के न्यायालय का एक अंतिम निर्णय है, और जब तक कि एक उचित कार्यवाही में पर्याप्त आधारों पर महाभियोग नहीं चलाया जाता है, एक पुरस्कार, जो नियमित रूप से इस तथ्य पर होता है, प्रस्तुत किए गए विवाद के गुण-दोष पर निर्णायक होता है, जब तक कि संभवतः पक्षों का इरादा नहीं होता है कि अवॉर्ड अंतिम और निर्णायक नहीं होगा। वास्तव में, एक अवॉर्ड में जीवन शक्ति के सभी तत्व होते हैं, भले ही इसे औपचारिक रूप से लागू नहीं किया गया हो और उसी विषय से संबंधित पक्षों के बीच मुकदमे में इस पर भरोसा किया जा सकता है। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, यह निष्कर्ष इस प्राथमिक सिद्धांत पर आधारित है कि पक्षकारों और उनकी निजता के बीच के रूप में, एक अवॉर्ड उस सम्मान का हकदार है जो अंतिम उपाय की अदालत के फैसले के कारण है। इसलिए, यदि पक्षकारों के बीच घोषित किए गए निर्णय को

वास्तव में, या कानूनी रूप से, वर्तमान विवाद से निपटा हुआ माना जा सकता है, तो दूसरा संदर्भ अक्षम होगा। यह स्थिति भी गंभीर रूप से विवादित नहीं रही है और न ही हो सकती है। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

32. इस न्यायालय ने माना कि उपरोक्त निर्णय ने कानून में सही स्थिति बताई और यह बाध्यकारी था। इस न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की अनुसूची । के पैराग्राफ 7 में आगे कहाः

"हम उल्लेख कर सकते हैं कि इन मामलों में अधिनियम की अनुसूची । के पैरा 7 के प्रावधानों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। यह पैरा प्रदान करता हैः

"7. अवॉर्ड अंतिम होगा और उनके अधीन दावा करने वाले पक्षों और व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगा। यदि अवॉर्ड अंतिम है और पक्षों के लिए बाध्यकारी है तो यह शायद ही कहा जा सकता है कि यह एक बेकार कागज है जब तक कि इसे अदालत का नियम नहीं बनाया जाता है।

एक अलग राय में न्यायमूर्ति हेगड़े ने कहा मध्यस्थता कार्यवाही को मोटे तौर पर दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण मध्यस्थता समझौते के साथ शुरू होता है और अवॉर्ड देने के साथ समाप्त होता है। और दूसरा चरण अवॉर्ड के प्रवर्तन से संबंधित है। मध्यस्थता अधिनियम की पहली अनुसूची के पैराग्राफ 7 में कहा गया है कि "अवॉर्ड अंतिम होगा और उनके तहत दावा करने वाले पक्षों और व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगा।" इसलिए पटना उच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसलों से सहमत होना संभव नहीं है कि एक निर्णय

जिसे न्यायालय की डिक्री नहीं बनाया गया है, उसका कानून में कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन मामलों का निर्णय लेने वाले विद्वान न्यायाधीशों ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि एक अवॉर्ड जिसे लागू नहीं किया जा सकता है वह एक वैध अवॉर्ड नहीं है और यह संपत्ति में कोई अधिकार पैदा नहीं करता है जो अवॉर्ड का विषय है। मेरी राय में यह सही तरीका नहीं है। अवॉर्ड उस संपत्ति में अधिकार पैदा करता है लेकिन उन अधिकारों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि अवॉर्ड को न्यायालय का आदेश नहीं बनाया जाता है। यह कहना एक बात है कि अधिकार नहीं बनाया जाता है, यह कहना पूरी तरह से अलग बात है कि बनाए गए अधिकार को आगे के कदमों के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]

34. इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 35 में "अंतिम और बाध्यकारी" खंड का मतलब सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए अंतिम नहीं है। अंतिमता किसी भी उपाय के अधीन है जो एक पीड़ित पक्ष के पास एक क़ानून या दूसरे उदाहरण में मध्यस्थता के लिए प्रदान किए गए समझौते के तहत हो सकता है। यह अवॉर्ड एक सीमित संदर्भ में बाध्यकारी है।

35. जब तक इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक भारत में दूसरी बार मध्यस्थता अपने आप में अमान्य होगी। यह देश के विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की एक लंबी कतार के खिलाफ होगा, जिन्होंने संस्थागत नियमों के तहत दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया की वैधता को स्वीकार किया है और यह विचार नहीं लिया है कि दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया अपने आप में अमान्य है। इस संबंध में कुछ हाल ही में श्री लाल महल लिमिटेड बनाम प्रोजेटो ग्रानो स्पा में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें अनाज और चारा व्यापार संघ, लंदन के अपील बोर्ड द्वारा एक अवॉर्ड पर विचार किया गया था और उसे बरकरार रखा गया था। इसी

तरह सुभाष अग्रवाल एजेंसी बनाम भीलवाड़ा सिंटलेटिक्स लिमिटेड मामले में दिल्ली हिंदुस्तान मर्कैंटाइल एसोसिएशन के नियम और विनियमों के तहत गठित एक अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय विचाराधीन था। कई अन्य उदाहरणों का हवाला दिया जा सकता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है। एक ही प्रभाव के लिए कई उच्च न्यायालयों के कई निर्णय हैं और हम दो-स्तरीय मध्यस्थता के सामान्य सिद्धांत की अंतर्निहित स्वीकृति में कोई त्रुटि नहीं देखते हैं।

पार्टी की स्वायत्तता

36. पार्टी की स्वायत्तता वस्तुतः मध्यस्थता की रीढ़ है। इस न्यायालय ने कई फैसलों में यह विचार व्यक्त किया है। भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक. के दो महत्वपूर्ण परिच्छेदों में इस न्यायालय ने संविदाकारी पक्षों के दृष्टिकोण से पक्ष की स्वायत्तता और वाणिज्यिक अनुबंधों में इसके महत्व पर विचार किया। रिपोर्ट के पैराग्राफ 5 में यह देखा गया था कि

> "पक्ष की स्वायत्तता मध्यस्थता में प्रेरक और मार्गदर्शक भावना होने के कारण, पक्ष अपने पूरे अनुबंध को नियंत्रित करने वाले तीन अलग-अलग कानूनों के अनुप्रयोग पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं-(।) अनुबंध का उचित कानून, (2) मध्यस्थता समझौते का उचित कानून, और (3) मध्यस्थता के संचालन का उचित कानून, जिसे लोकप्रिय और कानूनी भाषा में "क्यूरियल लॉ" के रूप में जाना जाता है। सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड में मध्यस्थता के लिए इन विभिन्न कानूनों की परस्पर क्रिया और अनुप्रयोग को इस न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप से समझाया गया है, जो उस दिशा में सबसे शुरुआती निर्णयों में से एक है और जिसका हाल

के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ सहित बाद के सभी निर्णयों में लगातार पालन किया गया है। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]

बाद में रिपोर्ट के पैराग्राफ 10 में, यह अभिनिर्धारित किया गया थाः "व्याख्या के मामले में, अदालत को व्याख्या के लिए आने वाले साधन के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोण बनाने होते हैं। विधायी प्रारूपण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और किसी अधिनियम, नियम या विनियमन को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न चरणों में इसकी जांच की जाती है। कानूनविदों या दस्तावेज़ लेखकों द्वारा मसौदा तैयार करने की एक और श्रेणी है जो पेशेवर रूप से योग्य हैं और इस क्षेत्र में अनुभवी हैं जैसे दस्तावेज़, संधियाँ, अदालत में निपटान, आदि। और फिर आम लोगों द्वारा बनाए गए दस्तावेजों की तीसरी श्रेणी है जिन्हें कानून या क्षेत्र में विशेषज्ञता का कोई ज्ञान नहीं है। दस्तावेज़ की कानूनी गुणवत्ता या पूर्णता तीसरी श्रेणी में तुलनात्मक रूप से कम है, दूसरे में उच्च और पहले में उच्च है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहली श्रेणी में व्याख्या की प्रक्रिया में, अदालतें कानून के उद्देश्य, उसके संदर्भ और पाठ को इकट्ठा करने का प्रयास करती हैं। दूसरी श्रेणी में भी, पाठ के साथ-साथ उद्देश्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और वसीयत जैसे दस्तावेजों की तीसरी श्रेणी में, यह केवल निष्पादक का इरादा है जो प्रासंगिक है। हमारे समक्ष मामले में, दोनों पक्षों के बीच निष्पादित एक अनुबंध होने के नाते, अदालत एक क़ानून की व्याख्या के लिए एक दृष्टिकोण नहीं अपना सकती है। अनुबंध की शर्तों को उस तरह से समझना होगा जिस तरह से पक्ष चाहते थे और उनका इरादा था। उस संदर्भ में, विशेष रूप से मध्यस्थता के समझौतों में, जहां पक्ष की स्वायत्तता कठोर मानदंड है, पार्टियों ने समझौते को कैसे तैयार किया, अभिव्यक्ति के स्पष्ट या व्याकरणिक अर्थ और समझौते में उचित स्थानों पर अभिव्यक्ति के उपयोग के अलावा, इरादे को समझने के लिए संकेतकों में से एक है। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]

37. भारत संघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड 29 में इस न्यायालय ने इस विचार को स्वीकार किया कि ए एंड सी अधिनियम के चार मूलभूत स्तंभ हैं और फिर रिपोर्ट के पैराग्राफ 16 में कहा गया हैः

"पहले स्तंभ का पहला और सर्वोपरि सिद्धांत "एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष, त्वरित और सस्ती सुनवाई" है। अनावश्यक देरी या खर्च मध्यस्थता के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। दिलचस्प बात यह है कि दूसरा सिद्धांत जिसे अधिनियम में मान्यता दी गई है, वह है प्रक्रिया के चयन में पार्टी की स्वायत्तता। इसका मतलब है कि यदि मध्यस्थता समझौते में एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिस पर पक्षकार सहमत हुए हैं, तो आम तौर पर इसका सहारा लेना होगा। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

38. अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के कानून और व्यवहार में भी यही दृष्टिकोण लिया गया है जिसमें कहा गया हैः

> "अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करने में दल की स्वायत्तता मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका न केवल राष्ट्रीय कानूनों में, बल्कि दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ संस्थानों के साथ-साथ न्यूयॉर्क कन्वेंशन और मॉडल लॉ जैसे अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों द्वारा भी समर्थन किया जाता है।

39. हालांकि, तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में लेखक एक कदम आगे बढ़ते हैं, प्रक्रिया के अलावा, वे कहते हैं कि पार्टी की स्वायत्तता पार्टियों को मूल कानून की अपनी पसंद रखने की अनुमति देती है। ऐसा कहा जाता हैः

> "सभी आधुनिक मध्यस्थता कानून पक्ष की स्वायत्तता को मान्यता देते हैं, अर्थात, पक्ष मध्यस्थता द्वारा हल किए जाने वाले विवाद के गुण-

दोष पर लागू मूल कानून या नियमों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। पार्टी की स्वायत्तता अनुबंध करने वाले पक्षों को एक अंतरराष्ट्रीय विवाद के लिए एक प्रतिकूल या अनुचित कानून के अनुप्रयोग से बचने का एक तंत्र प्रदान करती है। यह विकल्प मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए बाध्यकारी है और होना चाहिए। अधिकांश मध्यस्थता नियमों में भी इसकी पुष्टि की गई है। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

40. चाहे जो भी हो, कानूनी स्थिति जैसा कि हम इसे समझते हैं, वह यह है कि मध्यस्थता समझौते के पक्षों को न केवल अनुसरण किए जाने वाले प्रक्रियात्मक कानून पर बल्कि मूल कानून पर भी निर्णय लेने की स्वायत्तता है। अधिकार क्षेत्र का चुनाव अनुबंध करने वाले पक्षों पर छोड़ दिया गया है। वर्तमान मामले में, पक्ष समझौते के खंड 14 के माध्यम से दो स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली पर सहमत हुए हैं और समझौते के खंड 16 में भारत के कानूनों के अनुसार किए गए अनुबंध के रूप में अनुबंध के निर्माण का प्रावधान है। हम दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत दोनों खंडों में से किसी में भी कुछ भी गलत नहीं देखते हैं।

सार्वजनिक नीति और दो-स्तरीय मध्यस्थता

41. अब जो सवाल उठता है वह है सार्वजनिक नीति और पार्टी की स्वायत्तता के बीच परस्पर क्रिया और इसलिए क्या दो स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली को अपनाना सार्वजनिक नीति के विपरीत है।

42. बरसों पहले, एमिकेबल सोसाइटी बनाम बोलैंड (फॉन्टलरॉय का मामला) में बरोज के अनुसार, जे कहा गया थाः सार्वजनिक नीति एक प्रतिरोधी घोड़ा है और जब आप इससे भटक जाते हैं, तो यह नहीं पता होता कि यह आपको कहाँ ले जाएगा।

शायद इस अनिश्चितता को दूर करने में सहायता करने के लिए, मस्टिल और बॉयड ने अदालतों द्वारा सार्वजनिक नीति के विपरीत माने जाने वाले प्रावधानों के चार वर्गों की पहचान की। वे हैंः (i) वे शर्तें जो निर्णय की मूल सामग्री को प्रभावित करती हैं; (ii) वे शर्तें जो न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र को बाहर करने या प्रतिबंधित करने का तात्पर्य रखती हैं; (iii) वे शर्तें जिनके लिए मध्यस्थ को अस्वीकार्य तरीके से संदर्भ का संचालन करने की आवश्यकता होती है; और (iv) वे शर्तें जो मध्यस्थ को ऐसी प्रक्रियाएं या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने का तात्पर्य रखती हैं जो विशेष रूप से न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। पक्षों के बीच समझौते का खंड 14 इनमें से किसी भी स्थिति के अंतर्गत नहीं आता है।

43. हमारे देश में, इस विषय पर मामले के कानून पर हाल ही में विस्तृत चर्चा की गई है और एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण में कहा गया है और इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक अवॉर्ड को अलग रखा जा सकता है यदि यह इसके विपरीत हैः

(क) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (ख) भारत का हित; या (ग) न्याय या नैतिकता, या (घ) यदि यह स्पष्ट रूप से अवैध है।

44. वर्तमान में हम केवल भारत की मौलिक या सार्वजनिक नीति से संबंधित हैं। एसोसिएट बिल्डर्स में भारत की मौलिक नीति के व्यापक वर्णन को मानते हुए भी हम दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली को पसंद करने और स्वीकार करने वाले पक्षों में कुछ भी मौलिक रूप से आपत्तिजनक नहीं पाते हैं। अनुबंध के पक्षों ने ए एंड सी अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान को पारित नहीं किया है और उन्हें पता था, या कम से कम उन्हें पता होना चाहिए था कि वे भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल द्वारा दिए गए निर्णय की

अंतिमता पर सहमत हो सकते थे। फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से और जानबूझकर इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुलह और मध्यस्थता के नियमों के अनुसार लंदन, यूके में दूसरे या अपीलीय मध्यस्थता पर सहमत होने का फैसला किया। ए एंड सी अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनुबंध करने वाले पक्षों को दूसरे उदाहरण या अपीलीय मध्यस्थता पर सहमत होने से रोकता है-या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से। इस तरह के किसी भी निषेध या आदेश को ए एंड सी अधिनियम में पढ़ा नहीं जा सकता है, सिवाय एक अनुचित और अजीब गलत निर्माण के और इसकी भाषा को एक लुप्त होने वाले बिंदु तक दबाए जाने के। हम इस कारण से चिंतित नहीं हैं कि पक्ष (एच. सी. एल. सहित) दूसरी बार मध्यस्थता के लिए सहमत क्यों हुए-तथ्य यह है कि उन्होंने ऐसा किया और वे उनके द्वारा किए गए समझौते से बाध्य हैं। एच. सी. एल. अपने द्वारा स्वेच्छा से, जानबूझकर और खुली आँखों से की गई एक गंभीर प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट सकता है।

45. हम एचसीएल के विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए तरीके से ए एंड सी अधिनियम को पढ़ने से इनकार करते हैं और मानते हैं कि पक्षों के बीच समझौते में मध्यस्थता खंड दूसरी बार मध्यस्थता के लिए सहमत पक्षों द्वारा भारत की मौलिक या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता है। हमारी चर्चा से यह पता चलता है कि जिस निर्णय को एच. सी. एल. द्वारा चुनौती दी जानी चाहिए, वह 29 सितंबर, 2001 को लंदन में मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय है।

निष्कर्ष

46. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारे सामने पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है। अपीलीय अधिनिर्णय के प्रवर्तन से संबंधित दूसरे प्रश्न पर विचार करने के लिए अपीलों को फिर से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

मामले स्थगित कर दिए गए।

निधि जैन

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक मनीष शर्मा द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है,एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।